ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-1* Issue-11* December-2016
Innovation The Research Concept

सतत विकास की ऐतिहासिक परिकल्पनाएं

खुशवन्त सिंह
शोध छात्र,
इतिहास विभाग,
डी0 एस0 बी0 परिसर,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल

सारांश

प्राचीन काल से ही मानव निरन्तर विकास की ओर अग्रसर रहा है, इसी का परिणाम है कि आज वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुचने के पश्चात मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे है,परन्तु इस विकास क्रम मे मानव ने प्रकृति के साथ अपने निजी स्वार्थ हेतु पर्याप्त छेडछाड़ की है। इस कारण आज यह चिंतनीय विषय है कि क्या इस तरह का विकास प्रकृति व मानव समाज की उत्तरजीविता के लिए लाभप्रद है? आज इस तरह के विकास की आवश्यकता है, जिससे प्रकृति को कम से कम क्षति हो तथा इस न्यूनतम क्षति के साथ प्राकृतिक संसाधनो का दोहन करते हुए विकास क्रम को जारी रखा जा सके। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे यह दृष्टव्य है कि अतीत मे जब भी मानव ने अपने विकास के लिए प्रकृति से छेडछाड़ की है उसे इसके प्रतिकूल परिणाम भुगतने पडे है। कृषि व ईधन हेतु वनो का अत्याधिक दोहन तथा वनो के इस अतिदोहन से जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से हरी भरी–भूमि का मरूस्थल मे बदल जाना और अंत मे परिणामस्वरूप कई सभ्यताओ का विलुप्त हो जाना, सतत विकास के विपरीत ऐतिहासिक उदाहरण है। प्रस्तुत लेख मे सतत विकास की इस संकल्पना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : सतत विकास, ऐतिहासिक परिकल्पनाए, प्रकृति, पंचवर्षीय योजनाएँ।

प्रस्तावना

विकास योजनाबद्ध ढंग से किये गये सृजनात्मक कार्य को कहते हैं। इसका ध्येय मानव की ज्ञान संपदा की वृद्धि करना होता है। इसमें मानव के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में एवं समाज के बारे में ज्ञान की वृद्धि भी शामिल है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र ''सतत विकास की ऐतिहासिक परिकल्पनाएं'' का उद्देश्य विकास कें मार्ग पर आने वाली समस्याओ को स्पष्ट करना एवं उन्हे दूर करने को किए गए प्रयासो पर प्रकाश डालना हैं।

वाणिज्य की दुनिया में किसी उत्पाद के विकास की परिकल्पना करने का प्रभाग अनुसंधान एवं विकास कहलाता है। इसका अर्थ है कि उत्पाद बनाने के लिये आवश्यक मूलभूत विज्ञान पता होना चाहिये या यदि इस ज्ञान का अभाव है तो उसकी खोज की जानी चाहिये। किन्तु यदि उत्पाद से सम्बंधित विज्ञान मौजूद है तो इस ज्ञान को एक उपयोगी उत्पाद में बदलना भी एक बड़ा कार्य होता है जिसे विकास कहते हैं। अलग शब्दों में विकास के लिये प्रौद्योगिकी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।जिसका मुख्य ध्येय उचित मूल्य, उचित आकार, उचित ऊर्जा–खपत आदि की प्राप्ति होती है।

ग्रामीण विकास

राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के प्रति कटिबद्ध राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप में कल्याणकारी योजनाओं का सृजन करता हुआ उन्हैं मूल रूप देने का भरसक प्रयास कर रहा है। गांवों मे बसने वाले भारत के सर्वांगीर्ण विकास की परिकल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती, जब तक कि गांवों एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुये सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। आज देश तीव्र गति से नियोजित विकास करते हुए अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाने हेतु प्रयासरत है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के वर्षों में देश ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुये विकास के अनेक सोपान चढ़ते हुये कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। एक ओर जहां सरकार विकास की गति को तीव्र से तीव्रतम करने के

लिये प्रयत्नशील है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक विपदायें विकास में बाधक न हों सकें इस बाबत भी सजग एवं सचेत रही है। इसके साथ ही संसाधनों की कमी एवं बदली हुयी जनसंख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्यायें भी सदैव बनी रही है। फलतः निर्धनता, बेरोजगारी और विषमता आदि समस्याओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सदैव आघात पहुँचता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों को न केवल विकास की मुख्य धारा से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है बल्कि ग्रामीण विकास हेतु विपुल संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में जन सुविधाओं का विस्तार रोजगार के अधिक अवसर एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधारी लाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और जातिगत पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किये गये है, लेकिन राजस्थान में ग्रामीण विकास को अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुये वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गयी। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे "विशिष्ट योजनाओं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग" का नाम दिया गया। एक अप्रैल 1999 से इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिलास्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद में विलय करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग है।

राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जहां एक ओर ग्रामीण विकास की 20 एवं पंचायतीराज की 9 से भी अधिक योजनाऐं क्रियान्वित कर विकासात्मक असन्तुलन को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षित प्राथमिकता देने की दृष्टि से स्थाई विकास को लक्ष्य में रखकर कमजोर और अपेक्षित वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी और संविधान के 73 वें संशोधन के उपरान्त नया पंचायतीराज अधिनियम 1994, 23 अप्रैल, 1994 से लागू कर राज्य को नया स्वरूप प्रदान किया गया है। जिसके तहत पंचायतीराज संस्थाओं को अनेक अधिकार प्रदान किये गये हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधीन ग्रामीण विकास की योजनाएं शासन सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज के माध्यम से किया जा रहा है।

संसाधनों का विकास

जहां कहीं भी स्थानीय समाज में समुदाय पर आधारित संगठन ने स्थानीय संसाधनों को विकसित करने की कोशिश की है वहां पर कम से कम तीन चार बातें तो हुई हैं। एक तो पानी की किल्लत में कमी आयी है, कृषि उत्पादकता बढ़ी है।, पर्यावरण विघटन की प्रक्रिया में गिरावट आयी है। लागों की जो माली हालत थी उसमें सुधार हुआ है। सबको लगता है कि उन्होने कुछ हासिल किया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पक्ष है जो किसी समाज को आगे बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप की ओर जो झुकाव है उसमें राजनैतिक इच्छाशक्ति की बहुत जरूरत है।

तकनीकी विकास

देश की स्वास्थ्य समस्याओं पर बहुत बड़ी धनराशि इस देश को खर्च करनी पड़ती है। और इसके पीछे युवाओं की बदलती जीवन शैली परिवार का दबाव, इंटरनेट का उपयोग जैसे कारण हमारी अस्त–व्यस्त जीवनचर्या ही बहुत हद तक जिम्मेदार है। पर्यावरण को प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभाव से बचाने के लिये दुनियाभर में प्रयास हो रहे हैं। प्रदूषण रोज बढ़ रहा है। इसे रोकने के उपायों पर हमेशा सोचने की जरूरत है। सड़कों पर दुपहिया, चार पहिया वाहनों को कम करने के लिये सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के मुख्य बिन्दुओं को सार्वजनिक करते हुये सुझाव आमंत्रित किये हैं। बीते ढाई दशकों में सुचना तकनीक, आर्थिकी और जीवनशैली में तेजी से बदलाव हुए हैं। ऐसे में प्रस्तावित नई नीति में मौजूदा और भावी उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से कई नये आयाम जोड़े गये हैं। उम्मीद् है कि सरकार बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों की राय पर समुचित संज्ञान लेते हुये ही नई नीति को अंतिम रूप देगी। ऐसे समय जब देशभर में उच्च शिक्षा राजनैतिक कारणों से विवादों में घिरती जा रही है। भारतीय छात्रों द्वारा उपग्रह निर्माण और उसका सफल प्रक्षेपण आशान्वित करता है कि संसाधन, सुविधायें और अवसर दिये जाये तो ऐसी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। एक साथ 20 सैटेलाइट लांच कर इसरो ने अपनी क्षमता को फिर साबित किया है। भारत अब सभी तरह के उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर हो गया है।

कृषि विकास

खेती और किसानी हमारे देश में इस समय मजबूरी का कार्य बन चुके है, जिसे उसकी स्थिति के कारण अन्य देशों के लोग हेय दृष्टि से देखते हैं।अगर भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित करना है तो फिर खेती को प्राथमिकता में लाना होगा। भारतीय खेती इस समय कई संकटों और चुनौतियों का सामना कर रही है। राष्ट्रीय किसान आयोग के लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए। सबसे पहले खेती को कैसे लाभ का पेशा बनाया जाय तथा पढ़े–लिखे लोग भी इसमें आये इस पर उसे ध्यान केन्द्रित करना होगा। बैंको से किसानों को मिलने वाले कृषि ऋण को लेकर कई भ्रांतियां हैं। बड़ी शिकायत यह रहती है कि ढेर सारे दस्तावेज बैंक में जमा करने पड़ते हैं। बैंको से कृषि ऋण को आसान बनाना राज्य

सरकार, केन्द्र सरकार, रिजर्व बैंक और बैंक प्रबंधन के हाथ में है। खेती में जोखिम प्रबंधक का समुचित प्रबंध नहीं है। फसल बीमा अभी भी हास्यास्पद बना हुआ है। बार–बार ऋण माफी की जगह उचित जल और भूमि प्रबंध, मजबूत फसल बीमा और प्रसंस्करण पर ध्यान देने की जरूरत है। यूपीए सरकार के दौरान जब 2013 में मल्टी ब्रांड रिटेल को विदेशी कम्पनियों के लिये खोला गया, तो इसका देशभर में विरोध किया गया था। विरोध करने वालों में तब भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। उस विरोध के कारण यूपीए सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े थे। पर आज केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने एक बार फिर भारत के रिटेल बाजार को विदेशी कम्पनियों के लिये खोल दिया है। सरकार ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की स्वीकृति दे दी है। प्रत्येक स्थिति में विदेशी पूंजी निवेश जोखिम का काम है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा मानव के क्रमबद्ध विकास के विभिन्न चरणो को स्पष्ट किया गया है तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामन्जस स्थापित करते हुए विकास के वर्तमान स्वरूप का वर्णन किया गया हैं।

संदर्भ ग्रथ सूची

1. *सिन्हा,वी.सी.,"आर्थिक विकास" 2014, पृष्ठ–222।*
2. *मिश्रा एंड पुरी, "भारतीय अर्थव्यवस्था", 2007, पृष्ठ–167।*
3. *रूद्रदत्त एंड सुन्दरम्, "भारतीय अर्थव्यवस्था" 2014, पृष्ठ–230।*
4. *झिंगन,एम.एल, "आर्थिक विकास",2007, पृष्ठ–118।*
5. *पटेल,प्रो. राजेश, "ग्रामीण विकास की रूपरेखा",2011, पृष्ठ–130।*
6. *यादव,जियालाल, "भारत में कृषि समस्याएं",1994, पृष्ठ–118।*
7. *चौहान,वी.सी, "कृषि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत एवं भारत में कृषि विज्ञान" 1996, पृष्ठ–243।*
8. *गणेशन, एस.एन., "अनुसंधान प्रविधिः सिद्धांथ और प्रक्रिया" 2007, पृष्ठ–118।*
9. *सिन्हा, डॉ. सच्चिदानन्द.,"क्षेत्रीय विकास की अवधारणा और उत्तराखण्ड",2012, पृष्ठ–230।*
10. *जोशी, भैयाजी, "ग्रामीण विकास की संकल्पना",1996, पृष्ठ–243।*